

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9, 1966 (चैत्र 19, 1888)

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9, 1966 (CHAITRA 19, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 मार्च 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th March 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
50	No.39-ITC (PN)/66, dated 18-3-66.	Ministry of Commerce.	Import policy for licensing of raw material/components for the manufacture of Radio Receivers, Transistor Radio Receivers Amplifiers and Car radios for the period April 1965-March 1966.
51	No. 4(1)-Admn./66, dated 21-3-66.	Cabinet Sectt.	Announcing the death of Sh. K. L. Ghei, Special Secretary, and Director General, Bureau of Public Enterprises.
52	No. CMW/1793, dated 21-3-66	Do.	Reconstitution of the National Defence Council.
53	No. 4(1)-Admn./66, dated 23-3-66.	Do.	A short profile of Shri K. L. Ghei, Special Secretary and Director General, Bureau of Public Enterprises.
54	No. P. N. (Italy Licensing)/1 of 1966, dt. 24-3-66.	Do.	Scheme for the licensing of Cotton textiles for export to Italy from India.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची

(CONTENTS)

पृष्ठ (Page)	पृष्ठ (Page)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. 311	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. 15
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी भूखसरो की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं .. 317	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूखसरो की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं .. 219
	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. —
	भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर सचिवियों की रिपोर्ट .. —

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 2—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	579	भाग III—खंड 2—एकत्रित कार्यालय कनकला द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ और नोटिस	131
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएँ	927	भाग III—खंड 3—मूल्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएँ	41
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	105	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएँ, जिसमें अधिसूचनाएँ, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	243
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक सच-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के सचिव तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ	233	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	87
		पूरक सं० 15—	
		2 अप्रैल 1966 का समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	497
		12 मार्च 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े	509
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	311	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	927
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	317	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	105
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	15	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	233
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	219	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	131
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	41
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	243
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	579	PART IV—Advertisement and Notices by Private Individuals and Private Bodies	87
		SUPPLEMENT No. 15—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 2nd April 1966	497
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 12th March 1966	509

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, श्रित्तियों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

मंत्रिमंडल सचिवालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1966

सं० 8/1/63-सिब्वंदी II—भारत सरकार ने आंकड़ा विषयक भारतीय राष्ट्रीय समिति को दिनांक 1 जनवरी 1966 से आगामी आदेश तक और दो वर्ष के लिए पुनर्गठित किया है। उसकी रचना निम्नलिखित है :—

- | | |
|---|------------|
| (1) डॉ० सी० आर० राय, | अध्यक्ष |
| निदेशक,
अनुसंधान एवं, प्रशिक्षण विद्यालय,
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। | |
| (2) प्रोफेसर पी० सी० महालनोबिस, | सदस्य |
| एफ० आर० एस०, निदेशक,
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। | |
| (3) डॉ० बी० एस० हुजूरबाजार, | सदस्य |
| गणित एवं सांख्यिकी के प्राध्यापक तथा
विभागाध्यक्ष, पूना विश्वविद्यालय,
पूना। | |
| (4) डॉ० एस० एस० श्रीखंडे, | सदस्य |
| गणित प्राध्यापक,
बम्बई विश्वविद्यालय,
164, बैकवे रिकलेमेशन, रोड नम्बर 3,
बम्बई-1। | |
| (5) डॉ० डी० बी० लहिरी, | सदस्य |
| भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,
कलकत्ता। | |
| (6) डॉ० वी० जी० पाणसे, | सदस्य |
| डॉ० पाणसे का बंगला,
तिलकवाडी,
नासिक-2।
(महाराष्ट्र राज्य) | |
| (7) डॉ० के० आर० नायर, | सदस्य-सचिव |
| निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
एवं पदेन संयुक्त सचिव,
सांख्यिकी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय,
नई दिल्ली। | |

2. पुनर्गठित समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

- (क) आंकड़ा विषयक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना,
(ख) निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना तथा सांख्यिकीय विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में से किसी पहलु के विकास में योग

देने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यों को प्रोत्साहन तथा योग देना :—

- अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान,
- अन्तर्राष्ट्रीय जीवांकीय संस्था,
- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थमितीय संस्था,
- कार्यकारी अनुसंधान संस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संघ,
- जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन विषयक अन्तर्राष्ट्रीय संघ (यूनियन); और
- गणितीय सांख्यिकीय संस्थान; और
- देश में सांख्यिकीय विज्ञान के विकास को प्रोत्साहन देना।

3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा समिति को पूर्ववत् सचिवालयीय सहायता दी जायेगी।

एम० बाल कृष्ण मेनन, उप-सचिव

बाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

सीमा शुल्क टैरिफ, आयात व्यापार नियंत्रण और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ नामावलि

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 1966

सं० 1(154) टी० आर० सी०/66—भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के संकल्प सं० 10(8)/63-भाट, तारीख 17 मार्च, 1964 का उपांतरण करके, भारत सरकार ने टैरिफ पुनरीक्षण समिति को आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची के पुनरीक्षण का कार्य सौंपने का विनिश्चय किया है।

2. तदनुसार, उपर्युक्त संकल्प में नीचे यथा उपदर्शित अपर संशोधन कर दिये जाएंगे:—

- (1) संकल्प के विषय के रूप में आये "सीमा शुल्क टैरिफ" शब्दों के स्थान पर नीचे लिखे शब्द रख दिये जाएंगे:—

"सीमा शुल्क टैरिफ, आयात व्यापार नियंत्रण और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ नामावलि"

- (2) पैरा 4 में उप-पैरा (5) के बाद नीचे लिखे उप पैरे जोड़ दिये जायेंगे:—

"(5 क) आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची में पण्यों के वर्गीकरण की परीक्षा और उसके पुनरीक्षण की सिफारिशों, विशेषतया निम्नलिखित को ध्यान में रख कर, करना:—

- (क) पस्तापित आयात टैरिफ अनुसूची, तथा टैरिफ और आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूचियों के निर्वाचन के बीच संगति की आवश्यकता;

(ख) आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची को आयात तथा निर्यात व्यापार में पण्यों के सांख्यिकीय वर्गीकरण के साथ सह समन्वित करने की आवश्यकता, जिससे कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति का अधिक विस्तार से निर्माण सुकर हो जाए;

(5ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची (अर्थात् केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लक्षण अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची) में अपनायी गई नामावलि की पड़ताल करना और उसमें यथोचित संशोधनों का मुद्दा देना; ऐसा करने में समिति:—

(क) सीमा शुल्क आयात टैरिफ अनुसूची और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची के बीच निकटतर संबद्धता की वांछनीयता की इस दृष्टि से जांच करेगी कि—

(i) दोनों अनुसूचियों के निर्वचन और प्रशासन में यावत्साध्य एक रूपता सुनिश्चित हो जाए, और

(ii) प्रतिशुल्कों के उद्ग्रहण में सन्देहों और कठिनाइयों का दूर किया जाना सुकर हो जाए;

(ख) इस प्रश्न की भी जांच करेगी कि क्या और किस विस्तार तक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची को, सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए, आयात और निर्यात व्यापार के आंकड़े रखने के लिये अपनायी गई पद्धति के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है।

(3) पैरा 5 के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जायेगा :—

“इसी प्रकार, समिति का सम्बन्ध नामावलि से होगा, न कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची में दी गई दर रचना से।”

(4) पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायेगा :—

“समिति भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर देगी जो कि सरकार विनिश्चित करे।”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्पूक्त व्यक्तियों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

ए० बी० वैकटेश्वरन, संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1966

शुद्धिपत्र

सं० 16(10)/64-ई० आई० (एम०)—भूतपूर्व उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) के इसी संख्या वाले संकल्प दिनांक 18 दिसम्बर, 1965 में :—

(1) श्री जे० एस० माथुर का पदनाम (जिनका नाम क्रम संख्या 3 पर है) “संभरण तथा निपटान उप-महानिदेशक” के बदले “पूर्ति और निपटान अतिरिक्त महानिदेशक” पड़ा जाये।

(2) क्रम संख्या 15 पर प्रकाशित “श्री पी० आर० नायक” के विद्यमान नाम के स्थान पर “श्री जी० एन० मेहरा”

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली दिनांक 25 मार्च 1966

संस्था

सं० 2-7/66-रिआर्ग० (सी० सी०)—श्री एस० जे० मजूमदार, अपर सचिव भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता (कृषि विभाग) मंत्रालय, को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रशासन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसका गठन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, कृषि विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) के संस्था संख्या 2-7/66 रिआर्ग० (सी० सी०), दिनांक 17 फरवरी 1966 द्वारा किया गया है।

आदेश

आदेश है कि इस संस्था की प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जायें।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्था भारतीय राजपत्र में जनसाधारण की सूची के लिए प्रकाशित किया जाए।

पी० एस० हरिहरन

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 1966

सं० 11-5/65—रिआर्ग० (सी० सी०)-ii—यतः केन्द्रीय सरकार ने भारतीय तिलहन समिति अधिनियम 1946 (1946 के 9) की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा लोक सभा की पूर्वानुमति के अनुसार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 11-5/65-रिआर्ग० (सी० सी०) (iv) दिनांक 18 मार्च 1966 के द्वारा घोषणा की कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत निमित्त भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति का, 1 अप्रैल 1966 से विघटन किया जायेगा।

और यतः उपरोक्त घोषणा के अनुसार 31 मार्च 1966 तक समिति के अधिकार में आई हुई समस्त धन राशियां तथा सम्पत्ति 1 अप्रैल 1966 से केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आ जाएगी।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त समिति की उन समस्त धन राशियों तथा अन्य सम्पत्ति को, जो कि सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी तथा जो 1 अप्रैल 1966 से केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य में आ जाएगी, कालान्तर में लिखे जाने वाले एक इकरारनामे की शर्तों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान, परिषद्, नयी दिल्ली को हस्तांतरित करने का निर्णय करती है। हस्तांतरण के इकरारनामों के स्वरूप का निश्चय कुछ समय पश्चात् किया जाएगा।

आदेश

आदेश है कि इस संस्था की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्था भारतीय राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

सं० 11-5/65-रिआर्ग० (सी० सी०) (ii)—यतः केन्द्रीय सरकार ने भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 के 10) की धारा 17 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा लोक सभा की पूर्वानुमति के अनुसार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 11-5/65-रिआर्ग० (सी० सी०) (iii) दिनांक 18 मार्च 1966 के द्वारा घोषणा की कि उपरोक्त

और यतः उपरोक्त घोषणा के अनुसार 31 मार्च 1966 तक समिति के अधिकार में आई हुई समस्त धन राशियाँ तथा सम्पत्ति 1 अप्रैल 1966 के केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आ जाएगी।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त समिति की उन समस्त धन राशियों तथा अन्य सम्पत्ति को, जो कि सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी तथा जो 1 अप्रैल 1966 से केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य में आ जाएगी, कालान्तर में लिखे जाने वाले एक इकरारनामों की शर्तों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को हस्तांतरित करने का निर्णय करती है। हस्तांतरण के इकरारनामों के स्वरूप का निश्चय कुछ समय पश्चात किया जाएगा।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारतीय राजपत्र जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

सं० 11-5/65 रिआर्ग (सी० सी०) (iii)—यतः केन्द्रीय सरकार ने भारतीय लाख कर अधिनियम, 1930 (1930 के 24) की धारा 7 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 11-5/65-रिआर्ग (सी० सी०) (i) दिनांक 18 मार्च 1966 के द्वारा घोषणा की है कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निमित्त भारतीय केन्द्रीय लाख कर समिति का 1 अप्रैल 1966 से विघटन किया जाएगा।

और यतः उपरोक्त घोषणा के अनुसार 31 मार्च 1966 तक समिति के अधिकार में आई हुई समस्त धन राशियाँ तथा सम्पत्ति 1 अप्रैल 1966 से केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आ जाएगी।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त समिति की उन समस्त धन राशियों तथा अन्य सम्पत्ति को, जो कि सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी तथा जो 1 अप्रैल 1966 से केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य में आ जाएगी, कालान्तर में लिखे जाने वाले एक इकरारनामों की शर्तों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नयी दिल्ली को हस्तांतरित करने का निर्णय करती है। हस्तांतरण के इकरारनामों के स्वरूप का निश्चय कुछ समय पश्चात किया जाएगा।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारतीय राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

सं० 11-5/65-रिआर्ग (सी० सी०) (IV)—यतः केन्द्रीय सरकार ने भारतीय कपास उपकर अधिनियम 1923 (1923 के 14) की धारा 14 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 11-5/65-रिआर्ग (सी० सी०) (ii) दिनांक 18 मार्च 1966 के द्वारा घोषणा की कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निमित्त भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का विघटन किया जाएगा।

और यतः उपरोक्त घोषणा के अनुसार 31 मार्च 1966 तक समिति के अधिकार में आई हुई समस्त धन राशियाँ तथा सम्पत्ति 1 अप्रैल 1966 से केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आ जाएगी।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त समिति की उन समस्त धन राशियों तथा अन्य सम्पत्ति को, जो कि सरकार द्वारा निश्चित

की जाएगी तथा जो 1 अप्रैल 1966 से केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य में आ जाएगी, कालान्तर में लिखे जाने वाले एक इकरारनामों की शर्तों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नयी दिल्ली को हस्तांतरित करने का निर्णय करती है। हस्तांतरण के इकरारनामों के स्वरूप का निश्चय कुछ समय पश्चात किया जाएगा।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारतीय राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

बी० पी० पाल, अपर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 1966

सं० एफ० 40-6/66-ई०-I—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 41/3(3)/64-ई-I दिनांक 14 जुलाई, 1964 तथा संख्या एफ० 2/15/64 ई-I तारीख 22 दिसम्बर, 1964 के सिलसिले में, शिक्षा आयोग की अवधि पहली अप्रैल, 1966 से 30 जून, 1966 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गयी है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सूचनार्थ भारतीय गजट में प्रकाशित किया जाये।

प्रेम कुपाल, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1966

सं० 22(22)/62 एस० आर०-II,—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 22(22)/62 एस० आर०-II,—दिनांक 27 सितम्बर 1965 के सिलसिले में, प्रो० आर० डी० मिश्र, प्रमुख-बनस्पति विज्ञान, बनारस-विश्वविद्यालय, वाराणसी को 'नेशनल कमेंटी फार बाइलोजिकल साइमज' के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है।

एम० एम० मल्होत्रा, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1966

सं०-एफ० 3(9)/65-एस० आर० आई०—दिनांक 22 सितम्बर 1965 तदनुसार भाद्र 31, 1887 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि श्री सविन्द्र चौधरी, वित्त मंत्री, भारत सरकार और श्री ओ० बी० अलगेमन, पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, भारत सरकार को तात्कालिक रूप से 31 मार्च 1968 तक के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा का सदस्य नामजद किया गया है।

एस० हुसैन जहीर, सचिव
भारत सरकार (पदेन)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1966

विषय:—केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन।

सं० एफ० 12-3/65(I)सी०-3—शिक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के संकल्प संख्या एफ० 12-1/63-सी०-3, दिनांक 2 फरवरी, 1963 का अधिलेखन करते हुए, शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 33-13/55, दिनांक 8 फरवरी, 1956 तथा 33-39/56-सी-3, दिनांक 31 अक्तूबर, 1956 के तिलसिले में एतद् द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि संग्रहालयों के पुनर्गठन तथा विकास के सम्बन्धित मामलों के बारे में भारत सरकार को सलाह देने के लिए, तथा देश के विभिन्न संग्रहालयों की गतिविधियों के साथ सरकार तथा जनता के निकट साहचर्य और विभिन्न संग्रहालयों के बीच निकट सम्पर्क बढ़ाने के लिए केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए:—

1. नाम :

बोर्ड का नाम केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड होगा।

2. निर्वाचन

बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा:—

- (i) सचिव, शिक्षा मंत्रालय, (संग्रहालय के इन्चार्ज) बोर्ड के अध्यक्ष (पदेन),
- (ii) बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से उपाध्यक्ष चुना जाएगा,
- (iii) भारत सरकार के चार से अधिक नामजद नहीं,
- (iv) (संग्रहालयों से संबंधित संयुक्त सचिव अथवा संयुक्त शिक्षा सलाहकार),
- (v) भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक,
- (xi) ललित कला अकादमी का एक नामित,
- (vii) निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, अथवा यदि वहां निदेशक नहीं है, तो संग्रहालय का सब से वरिष्ठ कार्यभारी अधिकारी,
- (viii) निदेशक, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, अथवा यदि वहां निदेशक नहीं है, तो संग्रहालय के सब से वरिष्ठ अफसर इन्चार्ज,
- (ix) निदेशक, राष्ट्रीय नव कला वीथी, नई दिल्ली, यदि वहां निदेशक नहीं है, तो वीथी के सब से वरिष्ठ तकनीकी कार्यभारी अधिकारी,
- (x) निदेशक, संग्रहालय के सब से वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, संग्रहालय के अनुभाग के कार्यभारी के रूप में अधिक सेवा के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी,
- (xi) कंप्यूटर, विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता,
- (xii) निदेशक, ग्रिस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ बेस्टर्न इंडिया, बम्बई।
- (xiii) प्रत्येक राज्य सरकार एक प्रतिनिधि नामजद करेगी, जो कि सामान्यतया राज्य संग्रहालय का संग्रहालयध्यक्ष (कंप्यूटर) होना चाहिए अथवा संग्रहालय क्षेत्र का कोई सक्रिय व्यक्ति,
- (xiv) संग्रहालयों के बारे में विशेष योग्यता रखने वाले तीन व्यक्तियों से अधिक नहीं—जो बोर्ड से जुड़े हों।
- (xv) सदस्य सचिव, भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।

टिप्पणी:—'कंप्यूटर' शब्द का जहां कहीं भी ऊपर प्रयोग हुआ है, उसका कबन 'निदेशक' से है अथवा संग्रहालय के सब से वरिष्ठ कार्यभारी से है, वही उसका पद कुछ भी हो।

4. पद की अवधि

(क) उपाध्यक्ष सहित सदस्यों के पद की अवधि, जिनमें अध्यक्ष तथा पदेन-सदस्य और बोर्ड के सचिव शामिल नहीं हैं, नामजदगी की तारीख से तीन वर्ष की होगी अथवा वह थोड़ी अवधि होगी जो बोर्ड की अवधि के माध-साध समाप्त हो। अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों की प्रयावधि तीन वर्ष की होगी अथवा जब तक होगी, जब तक, जिस उत्तम गुण के कारण वे बोर्ड के सदस्य बने हैं—पद ग्रहण करते रहें—जो भी कम हो। सचिव बोर्ड के संस्थापन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक सरकार चाहे पद ग्रहण करेगा—इसमें जो भी कम हो। आकस्मिक खाली जगह पर नामजद किए गए सदस्य के पद की अवधि वही होगी, जब तक मौलिक सदस्यता की अवधि समाप्त नहीं होती है।

(ख) नामजद सदस्य पुनः नामजदगी के लिए बांछनीय होंगे।

5. कार्य

सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट संग्रहालयों सम्बन्धी सभी मामलों पर बोर्ड भारत सरकार, राज्य सरकार तथा भारत के संग्रहालयों को सलाह देगी और सामान्यतया संग्रहालयों के सुधार, पुनर्गठन, लोकप्रियता तथा उनके विकास के सम्बन्ध में परामर्श भी देगी।

6. बैठकें

जब अध्यक्ष जरूरी समझना बोर्ड की बैठक बुलाएगा। परन्तु एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। कम से कम एक तिहाई सदस्यों के मांग करने पर विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं, बशर्ते कि मीटिंग संयोजित करने से कम से कम एक माह पहिले, मांग सचिव को अधिग्रहण हो जाती है और प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य का स्पष्ट विवरण साथ में शामिल किया जाता है।

7. बैठकों की सूचना

सचिव, बैठक से कम से कम 15 दिन पहिले, सदस्यों को कार्य सूची के साथ, बैठक की सूचना भेज देगा।

8. कोरम (गवर्नरक संख्या)

कोरम को वैधानिक रूप देने के लिए कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित होंगे। यदि कोरम कम है, तो बैठक स्थगित हो जाएगी। मीटिंग स्थगित करने के लिए कोरम लागू नहीं होगा।

9. स्थायी तथा तदर्थ समितियां

(1) बोर्ड स्थायी अथवा तदर्थ समितियां बनाने के लिए स्वतन्त्र होगी और उन व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं बल्कि उन्हें उन समस्याओं का—जिन्हें कमेटी जांच के लिये जरूरी समझती है—विशेष ज्ञान तथा अनुभव है, उन्हें तदर्थ समिति की नियुक्ति के लिए बोर्ड को अधिकार होगा,

- (2) बोर्ड द्वारा स्थायी समिति के चुनाव के अपूर्ण काम को, पहली स्थायी समिति के ऐसे सदस्य, जो कि नव गठित बोर्ड में लौट आये हैं, समिति के कृत्यों को पूरा करेंगे,
- (3) नये सदस्यों की विनियुक्ति अपूर्ण होने से उपर्युक्त पैरा के उपपैरा (xi) के अधीन, पहली बोर्ड से जुड़े सदस्य, नई बोर्ड की पहली बैठक के समाप्त होने तक नई बोर्ड के सदस्य रहेंगे।

10. विघटन तथा पुनर्गठन

भारत सरकार की इच्छानुसार किसी भी समय बोर्ड को भंग किया जा सकता है अथवा उसे पुनर्गठित किया जा सकता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारतीय गजट में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक 28 मार्च 1966

सं० एफ०-12-3/65(II)सी-3—भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय संकल्प संख्या एफ-12-3/65 सी० 3, दिनांक 28 मार्च, 1966 के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्ति 28 मार्च, 1966 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड के सदस्य नामजद किए गए हैं :—

I. संकल्प पैरा 3 के खण्ड (iii) के अधीन (भारत सरकार से नामित) :—

1. श्री रामकृष्ण दाम,
अवैतनिक निदेशक,
भारत कला भवन,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।
2. डा० (श्रीमती) ग्रेस मोर्ले,
नयी दिल्ली।
3. श्री कर्ल जे० खाण्डालवाला,
मिन्सबर्गो, 63 बोर्ली मीफेम,
बम्बई-18।
4. डा० एस० नूरुल हसन,
इतिहास विभाग के प्रमुख,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

II. संकल्प के पैरा 3 के खण्ड (vi) के अधीन (सहित कला अकादमी के नामित) :—

श्री जी० बेंकटाचलम,
6-मैट जोहन्स रोड, बंगलौर।

III. संकल्प के पैरा 3 के खण्ड (xiii) के अधीन (राज्य सरकार के नामित) :—

1. आन्ध्र प्रदेश . श्री एम० ए० बहीद खां,
पुरातत्व तथा संग्रहालय के
निदेशक,
हैदराबाद।
2. आसाम . श्री प्रेमधर चौधरी
क्युरेटर,
आसाम राज्य संग्रहालय,
गोहाटी।

3. बिहार . श्री पी० एस० गुप्ता,
क्युरेटर,
पटना संग्रहालय,
पटना।
4. गुजरात . श्री बी० एल० देवकार,
निदेशक,
संग्रहालय तथा चित्रवीथी,
बड़ौदा।
5. केरल . श्री के० परमेश्वरन पिल्ले,
निदेशक,
स्पृजियम एण्ड जू
केरल सरकार,
त्रिवेन्द्रम।
6. मध्य प्रदेश . श्री बालचन्द्र जैन,
उपनिदेशक,
संग्रहालय,
रायपुर।
7. मद्रास . श्री एम० टी० सत्यमूर्ति,
निदेशक,
संग्रहालय,
मद्रास।
8. महाराष्ट्र . डा० एम० जी० दीक्षित,
निदेशक,
अभिलेखागार तथा ऐति-
हासिक स्मारक,
बम्बई।
9. मैसूर . श्री के० मानिक्यम,
क्युरेटर,
बंगलौर संग्रहालय,
बंगलौर।

संकल्प के पैरा 3 के खण्ड (xv) के अधीन (सदस्य सचिव) :—
उप-सचिव (सांस्कृतिक प्रभाग)
शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली।

टी० एस० कृष्णामूर्ति, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1966

विषय :—राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद्।

सं० एफ० 1-2/66-यू० 3—उपर्युक्त विषय पर शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 1-2/64 यू० 3, दिनांक 30 दिसम्बर 1965 के क्रम में, यह अधिसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् की कार्याविधि 1 अप्रैल, 1966 से और आगे तीन मास की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

जी० के० चन्द्रीरमानी, अपर सचिव

परिवहन और विमानन मंत्रालय

परिवहन, नौवहन और पर्यटन विभाग

(परिवहन पक्ष)

संस्थाप

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1966

सं० 21-टी० (42)/64—परिवहन और विमानन मंत्रालय (परिवहन, नौवहन और पर्यटन विभाग) में परिवहन अनुसंधान के निदेशक डा० बी० जी० भाटिया को इस मंत्रालय की संस्थाप सं० 21-टी० (42)/64, दिनांक 6 सितंबर 1965 के द्वारा स्थापित की गई सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के सदस्य के रूप में तुरंत मनोनीत किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाना है कि संस्थाव की एक प्रति समस्त संबद्ध को भेज दी जाये और यह भी कि सामान्य सूचना के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

(संस्थाव)**पत्तन**

दिनांक 28 मार्च 1966

म० 2-पी० जी० (55)/65—भारत सरकार को काडला पत्तन की 1964-65 की प्रशासन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । रिपोर्ट के मुख्य तथ्यों का पुनर्विलोकन नीचे किया जा रहा है —

(1) वित्तीय परिणाम

(क) **पत्तन निधि**—विचाराधीन वर्ष में पत्तन की राजस्व आय (कनिहारी खाते की आय को छोड़कर) 121 12 लाख रुपये रही । इसकी तुलना में 1963-64 में 114 42 लाख रुपये की आय हुई थी । अधिक आय होने का कारण कुछ तो यह है कि पत्तन खाते के साथ उपनगर खाता मिलाया गया और कुछ यह कि भूमि और इमारतों में अधिक आय हुई ।

(कनिहारी खाते के व्यय को और मूल्य ह्रास निधि राजस्व आरक्षित निधि और पूजी खाते के अशदानों को छोड़कर) विचाराधीन वर्ष में व्यय 82 63 लाख रुपया हुआ । इसके विपरीत 1963-64 में 62.25 लाख रुपया व्यय हुआ । कार्यचालन व्यय (मूल्य ह्रास निधि, राजस्व आरक्षित निधि और पूजी खाते में रखी गयी राशियाँ को छोड़कर) सामान्य खाते के अंतर्गत की आय का 68 प्रतिशत रहा, इसके विपरीत गत वर्ष यह राशि 55 थी । खर्च में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह था कि निकर्षण, बिजली और जल के बकाया खर्च उपनगर के राजस्व व्यय विलीनीकरण, महगाई भत्ते में वृद्धि, निर्वाह निधि के व्याज के शेष इत्यादि पर अधिक खर्च हुआ । 1964-65 में मूल्य ह्रास निधि, राजस्व आरक्षित निधि और पूजी खाते में क्रमशः 55 51 लाख रुपये, 22 50 लाख रुपये और 40 00 लाख रुपये का अशदान दिया गया ।

(ख) **कनिहारी खाता**—1964-65 में कुल आय और व्यय क्रमशः 3 48 लाख रुपया और 2 43 लाख रुपया (मूल्य ह्रास निधि और कनिहारी खाते के 8,000 रुपये के अशदान को छोड़कर) हुआ । इस प्रकार 1 05 लाख रुपये का अधिशेष रहा । 1963-64 में 1 लाख रुपये का अधिशेष था । उस वर्ष कुल आय और व्यय क्रमशः 2 80 लाख रुपया और 1 80 लाख रुपया था ।

(ग) **ऋण**—1964-65 के वित्तीय वर्ष के अंत में पत्तन प्रशासन पर सरकार का 16 77 करोड़ रुपये का ऋण बाकी था । यह ऋण पत्तन प्रशासन को हस्तान्तरित की गई परिसंपत्ति और पूंजीगत कार्यों के खर्च को पूरा करने के लिये दिये गये 22 लाख रुपये के ऋण के कारण हुआ था । इस ऋण राशि में भूतपूर्व कच्छ सरकार से प्राप्त 26.74 लाख रुपये की परिसंपत्ति भी शामिल है ।

(2) यातायात :

(क) **व्यापार**—1964-65 में काडला पत्तन द्वारा हुआ यातायात 1963-64 में हुये यातायात की तुलना में निम्न सारणी में दिया जा रहा है —

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल यातायात
(लाख मीटरी टना में)			
1963-64	14.91	2.88	17.79
1964-65	20.54	2.58	23.12

विचाराधीन वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 5 63 लाख मीटरी टन यानी 37 8 प्रतिशत अधिक आयात हुआ । अधिक आयात होने का मुख्य कारण यह था कि खाद्यान्न और मशीनों का अधिक आयात हुआ । ऊर्ची धातु, कपाम, ऊन, इत्यादि की यातायात में कमी होने के कारण 1964-65 में 1963-64 की अपेक्षा 0 30 लाख मीटरी टन कम निर्यात हुआ ।

(ख) **नौबहन**—1964-65 में पाल पोतो को छोड़कर कुल 28 87 लाख टन भार के 343 जहाज इस पत्तन पर आये । इसके विपरीत 1963-64 में कुल 24 26 लाख टन भार के 297 जहाज आये थे ।

27412 64 कुल टन भार का 224 40 मीटर लंबा, 31 26 मीटर घन वाला और आगे से 9.69 मीटर और पीछे से 9 75 मीटर डुबाव वाला एम० टी० "माट वेनान विक्टरी" नामक जहाज इस पत्तन पर 1964-65 में आने वाले जहाजों में से सब में बड़ा और लंबा जहाज था ।

14462 82 कुल टन भार का 174 65 मीटर लंबा और आगे से 10 11 मीटर और पीछे से 10 11 मीटर डुबाव वाला एम० एम० कोलम्बिया, नामक जहाज इस पत्तन पर 1964-65 आने वाले जहाजों में से सब से अधिक डुबाव वाला जहाज था ।

(3) **श्रमिक**—1964-65 में श्रमिक स्थिति सतोषजनक बनी रही ।

(4) **पूंजीगत निर्माण कार्य**—विचाराधीन वर्ष में मत्स्य घाट का निर्माण कार्य पूरा किया गया । पाचवी मालवर्ष निकर्षण को छोड़कर पूरी हो गयी है और इसके फलस्वरूप 1125 फुट पर घाट की ओर सुविधा हो गयी । भूमि-जल जाच प्रयोगशाला और फोटोग्राफ सैकशन का क्रियाकलाप पूर्ववत् होता रहा । भूमि जाच के अंतर्गत काडला पर 327 क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में छिद्र किये गये ।

(5) **कल्याणकारी क्रियाकलाप**—विचाराधीन वर्ष में पत्तन अपने कर्मचारियों को इस प्रकार की विभिन्न सुख सुविधायें देता रहा—आवास, क्लब, कान्टीन, चिकित्सा सुविधायें इत्यादि । एक सहकारी उधार समिति की स्थापना की गयी है और वह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है ।

(6) विचाराधीन वर्ष में गांधीधाम उपनगर का विकास कार्य सतोषजनक ढंग से होता रहा ।

(7) **सराहना**—सरकार विचाराधीन वर्ष में पत्तन द्वारा किये गये कार्य की सराहना करती है ।

आदेश

आदेश दिया गया है कि इस संस्थाव की एक प्रतिलिपि सभी संबद्धों को भेज दी जाये और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

के० सी० मादप्पा, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय**संकल्प**

नई दिल्ली-1, दिनांक 30 मार्च 1966

राष्ट्रीय एकता और भावात्मक समन्वय पर सर्वोत्तम**कथा (रूपक) चित्र के लिए नगद पुरस्कार**

म० 7/17/65-एफ० (आई०)—देश में राष्ट्रीय एकता और भावात्मक समन्वय को बढ़ावा देने वाले कथा चित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 20,000/- रुपये का नगद पुरस्कार प्रारम्भ किया है ।

2. यह पुरस्कार कैलेंडर वर्ष 1966 में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित फिल्मों में से उपरोक्त विषय के सर्वोत्तम कथा चित्र को दिया जायेगा।

3. पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों की तिथि सरकार निर्धारित करेगी, जो दिसम्बर, 1966 में अधिसूचित की जायेगी।

4. पुरस्कार के पात्र केवल वे ही चित्र होंगे, जिन्हें भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा प्रदत्त फिल्मों के लिए कोई राजकीय पुरस्कार प्राप्त हुआ होगा या जो पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने की तारीख तक 12 मप्ताह चल चुकी होगी।

5. इस पुरस्कार के लिए फिल्मों की प्रविष्टि पर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के संकल्प संख्या 7/19/64-एफ० आई० तारीख 21 नवम्बर, 1964 में अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित नियम यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे, जो फिल्मों के राजकीय पुरस्कार के संबंध में लागू होते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

देस राज खन्ना, अव्वर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th March, 1966

CORRIGENDUM

No. 32-Pres./66.—In this Secretariat Notification No. 18-Pres./65, dated the 26th January 1965, published in Hindi and in English in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 13th March, 1965—

On page 110, Serial 20

For "5740093 राइफलमैन तोपबहादुर राणा,
गोरखा राइफल्स।"

Read "5740095 राइफलमैन तोपबहादुर राणा,
गोरखा राइफल्स।"

On page 128, Serial 20

For "5740093 Rifleman TOPBAHADUR RANA,
The Gorkha Rifles".

Read "5740095 Rifleman TOPBAHADUR RANA,
The Gorkha Rifles".

V. J. MOORE, Dy. Secy. to the President.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 22nd March 1966

No. 8 1/63-Estt.II.—The Government of India have reconstituted the Indian National Committee for Statistics for a further period of two years with effect from 1st January 1966, with the following composition :—

Chairman

- (1) Dr. C. R. Rao,
Director,
Research and Training School,
Indian Statistical Institute,
Calcutta.

Members

- (2) Prof. P. C. Mahalanobis, F.R.S.,
Director, Indian Statistical Institute,
Calcutta.
- (3) Dr. V. S. Huzurbazar,
Professor and Head of the Department
of Mathematics and Statistics,
University of Poona,
Poona.
- (4) Dr. S. S. Shrikhande,
Professor of Mathematics,
Bombay University,
164, Backbay Reclamation,
Road No. 3, Bombay-1.
- (5) Dr. D. B. Lahiri,
Indian Statistical Institute,
Calcutta.
- (6) Dr. V. G. Panse,
Dr. Panse's Bungalow,
Tilkwadi,
Nasik-2 (Maharashtra State).

Member-Secretary

- (7) Dr. K. R. Nair,
Director, Central Statistical
Organisation, and *ex-officio*
Joint Secretary, Deptt. of Statistics,
Cabinet Secretariat, New Delhi.

2 The objects of the reconstituted Committee will be—

- (a) to promote international cooperation in statistics;
- (b) to liaise with the following international statistical organisations and to encourage and support international statistical activities likely to contribute to the development of statistical science in any of its aspects :—

- (i) International Statistical Institute,
- (ii) International Biometric Society,

(iii) International Econometric Society,

(iv) International Federation of Operational Research Society,

(v) International Union of Scientific Study of Population; and

(vi) Institute of Mathematical Statistics;

and (c) to promote development of statistical science in the country.

3. The Secretarial assistance to the Committee will continue to be provided by the Central Statistical Organisation.

M. BALAKRISHNA MENON, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 25th March 1966

No. F.3(20)-BC/66.—It is hereby notified that, with effect from the 1st April 1966, the Central Government work at Kanpur, which has hitherto been conducted by the State Bank of India, shall be taken over and conducted by the Kanpur Office of the Reserve Bank of India.

V. SWAMINATHAN, Under Secy.

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi-2, the 21st March 1966

No. F.3(1)-EV/66.—The Government of India have recently taken several measures to alleviate the distress of families of Central Government servants who die in service. The existing benefits include a Family Pension Scheme which ensures pension for life for the family of a Government servant who dies after a year's service. In case the Government servant had put in a service of at least 7 years prior to his death the family pension is doubled, subject to the limit of half the last pay drawn, for the first few years.

2. There also exists a Compassionate Fund of the Government of India which is intended for the relief of the families of Government servants if they are left in indigent circumstances on account of the premature death of the person upon whom they depended for support. The assistance from the Fund is, however, restricted to those who have not received any other form of death benefits, such as Contributory Provident Fund, gratuity, or family pension. Cases occasionally do arise where, in spite of the death benefits received by the family, the dependents continue to be in indigent circumstances or have special needs for which *ex-gratia* financial assistance is necessary. It has accordingly been decided to modify the Compassionate Fund Rules. The revised Rules are published as Annexure to this Resolution.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. C. KATOCH, Jt. Secy.

New Delhi, the 26th March 1966

No. 1493-PTI/66.—The President hereby makes the following further amendments in the rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurances, namely :—

In the said rules,—

1. For the penultimate sentence of rule 36, the following sentence shall be substituted, namely :—

"As soon as the connection of the insured person ceases with the Government, he should apply to the Postmaster-General for a Premium Receipt Book informing him of the name of the office at which the last premium while in Government service was deducted and the Post Office at which he desires to pay future premia in cash. A copy of this application should also be endorsed to the Postmaster of the place

at which future payments of premia are desired to be made in cash. If the Premium Receipt Book is not received by the time the next premium after his quitting Government service falls due, he should pay the amount by the due date in cash at the selected Post Office producing a certificate from his last Disbursing Officer in the form appended at the end of this rule. In such a case the concerned Postmaster would grant a receipt for the amount in form ACG-67. Subsequent premia will be paid in cash on production of the receipt for the previous month's premium, till the Premium Receipt Book is received by him. Thereafter the due premia shall be paid on production of the Premium Receipt Book and receipts for the amount will then be given only in the Premium Receipt Book.”;

2. Rule 37 of the said rules shall be omitted;

3. In rule 38 of the said rules for the word “Director” the word “Postmaster-General” shall be substituted;

4. In rule 42 of the said rules,—

(a) for clause (vi) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :—

“(vi) On the very date the amount of loan is finally repaid, the Postmaster concerned shall send an intimation to the Postmaster-General giving particulars as to the amount repaid, the date of repayment, the name of the insurant and the numbers of his policy and loan account. The insurant is advised in his own interest to send a separate intimation of final repayment of his loan to the Postmaster-General. On receipt of the above intimation, interest chargeable upto the end of the month of final repayment (provided that interest on the loan has already been charged for at least one half-year) shall be calculated by the Postmaster-General and communicated to the insurant under registered post. The insurant shall be required to pay the amount of interest at any Head or Sub Post Office within twenty-one days from the date of issue of intimation by the Postmaster-General”.

(b) in sub-rule (2), for the words “The Postmaster-General shall also calculate the amount of loan admissible in respect of the policy on the date of application. In the case of Base, Burma and Defence policies the Postmaster-General shall obtain the loan admissibility report from the Deputy Director, Postal Life Insurance, Calcutta. Thereafter the Postmaster-General shall sanction the loan if admissible, on the conditions stated above.”, the following words shall be substituted, namely :—

“He shall also calculate the amount of loan as admissible on the date of application and sanction the loan, if admissible, on the conditions stated above”.

The 29th March 1966

No. 1383-PTI/66.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.3(40)-NS/58 dated the 19th December, 1958.

In the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules 1959, in rule 11(a), between the words “into the account” and “may be allowed”, the words “not being an account treated as discontinued under rule 6,” shall be inserted.

C. B. GULATI, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th March 1966

No. 16(10)/64-EI(M).—In the erstwhile Ministry of Industry and Supply (Department of Industry)'s Resolution of even number dated the 18th December 1965—

- (i) the designation of Shri J. S. Mathur (whose name appears at Sl. No. 3) may be read as “Additional Director General of Supplies & Disposals” instead of “Deputy Director General of Supplies and Disposals”;
- (ii) for the existing name “Shri P. R. Nayak” appearing at Sl. No. 15, the name “Shri G. N. Mehra” may be substituted.

J. S. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF MINES AND METALS

New Delhi, the 29th March 1966

No. C44-7(1)/66.—The Government of India have decided that the tenure of the Coal Advisory Council which was set up in the late Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Department of Mines and Metals) Resolution No.

C6-8(1)/62 dated the 9th March 1964, for a term of two years, be extended for a further period of two years. It is also notified for general information that the composition of the Council will now be as under :—

COMPOSITION

Chairman

Minister for Mines and Metals.

Members

1. The Secretary, Ministry of Mines and Metals.
2. The Secretary, Ministry of Iron and Steel.
3. The Secretary, Ministry of Industry.
4. The Secretary, Ministry of Irrigation and Power.
5. The Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Co-ordination.
6. The Secretary, Ministry of Supply & Technical Development.
7. A representative of the Planning Commission.
8. Member (Transportation), Railway Board.
9. The Secretary, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Deptt. of Labour & Employment).
10. The Secretary, Ministry of Petroleum & Chemicals.
11. The Coal Controller.
12. The Managing Director, National Coal Development Corporation Limited.
13. The Managing Director, Singareni Collieries Company Ltd.
14. The Chairman, Neyveli Lignite Corporation Limited.
15. The Director General, Council of Scientific and Industrial Research.
16. The Director, Central Fuel Research Institute, Dhanbad.
17. The Director, Regional Research Laboratory, Hyderabad.
18. The Director, Central Mining Research Station Dhanbad.
19. The Director, National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur.
20. The Chief Inspector of Mines, Dhanbad.
21. The Joint Working Committee of the coal industry, representing Indian Mining Association, Indian Colliery Owners' Association, Indian Mining Federation and the M.P. & Vidarbha Mining Association (4 representatives).
22. A representative of the coal industry in Assam.
23. Soft Coke Producers' Collieries Association.
24. Coal Consumers' Association of India.
25. Indian Coal Merchants' Association.
26. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry.
27. Associated Chambers of Commerce & Industry.
28. A representative of labour.
29. Indian Mine Managers' Association.
30. One representative each of the Governments of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Maharashtra, and Assam, representing coal producing States.
31. One representative each of Governments of Uttar Pradesh, Punjab, Mysore, Rajasthan, Kerala, Gujarat and Madras, representing major coal consuming States.

N. D. GUPTA, Jr. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

I.C.A.R.

RESOLUTIONS

New Delhi, the 25th March 1966

No. 2-7/66-Reorgn.(CC).—Shri S. J. Majumdar, Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) is appointed as a member of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research, as constituted vide Resolution No. F.2-7/66-Reorgn.(CC), dated the 17th February, 1966 of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation, Department of Agriculture (ICAR).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 29th March 1966

No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(i).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 16 of the Indian Oilseeds Committee Act, 1946 (9 of 1946), and with the previous approval of the House of the People, have, by Notification No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(iv) dated the 18th March, 1966, published in the Official Gazette, declared that with effect from 1-4-1966, the Indian Central Oilseeds Committee, constituted under section 4 of that Act, shall be dissolved;

And whereas by the making of the said declaration, all funds and other property vested in the Committee on the 31st March, 1966, shall vest in the Central Government with effect from 1-4-1966.

Now, the Central Government hereby resolves to transfer such funds and other property of the said committee, as may be decided by the Government which shall be vested in the Central Government with effect from 1st April, 1966, to the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, on terms and conditions to be embodied in the deeds of transfer to be executed later. The nature of the deeds of transfer will also be determined later.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(ii).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 17 of the Indian Coconut Committee Act, 1944 (10 of 1944), and with the previous approval of the House of the People, have, by Notification No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(iii) dated the 18th March, 1966, published in the Official Gazette, declared that with effect from 1-4-1966, the Indian Central Coconut Committee, constituted under section 4 of that Act, shall be dissolved;

And whereas by the making of the said declaration, all funds and other property vested in the Committee on the 31st March, 1966, shall vest in the Central Government with effect from 1-4-1966.

Now, the Central Government hereby resolves to transfer such funds and other property of the said committee, as may be decided by the Government, which shall be vested in the Central Government with effect from 1st April, 1966, to the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, on terms and conditions to be embodied in the deeds of transfer to be executed later. The nature of the deeds of transfer will also be determined later.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(iii).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Lac Cess Act, 1930 (24 of 1930) have, by Notification No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(i), dated the 18th March, 1966, published in the Official Gazette, declared that with effect from the 1st April, 1966, the Indian Lac Cess Committee, constituted under that Act, shall be dissolved;

And whereas by the making of the said declaration, all funds and other property vested in the Committee on the 31st March, 1966, shall vest in the Central Government with effect from the 1st April, 1966.

Now, the Central Government hereby resolves to transfer such funds and other property of the said committee, as may be decided by the Government, which shall be vested in the Central Government with effect from 1st April, 1966, to the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, on terms and conditions to be embodied in the deeds of transfer to be executed later. The nature of the deeds of transfer will also be determined later.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(iv).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 14 of the Indian Cotton Cess Act, 1923 (14 of 1923) have, by Notification No. 11-5/65-Reorgn.(CC)(ii), dated the 18th March, 1966, published in the Official Gazette, declared that

with effect from the 1st April, 1966, the Indian Central Cotton Committee, constituted under that Act, shall be dissolved;

And whereas by the making of the said declaration, all funds and other property vested in the Committee on the 31st March, 1966, shall vest in the Central Government with effect from the 1st April, 1966.

Now, the Central Government hereby resolves to transfer such funds and other property of the said committee, as may be decided by the Government which shall be vested in the Central Government with effect from 1st April, 1966, to the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, on terms and conditions to be embodied in the deeds of transfer to be executed later. The nature of the deeds of transfer will also be determined later.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. P. PAL, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

RESOLUTION

New Delhi, the 26th March 1966

No. F.40/6/66.E.I.—In continuation of this Ministry's Resolutions No. F.41/3(3)/64.E.I., dated the 14th July, 1964, and No. F.2-15/64.Estr.I dated the 22nd December, 1964, the term of the Education Commission has been extended by three months from the 1st April, 1966, to the 30th June, 1966.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for information.

PREM KIRPAL, Secy.

New Delhi, the 26th March 1966

No. 22(22)/62-SR.II.—In continuation of this Ministry's Notification No. 22(22)/62-SR.II dated the 27th September, 1965, Prof. R. D. Misra, Head of the Department of Botany, Banaras University, Varanasi, has been included as a member in the National Committee for Biological Sciences.

M. M. MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi-1, the 26th March 1966

No. F.3(9)/65-SR.I.—In continuation of Notification No. F.3(9)/65-SR.I dated the 22nd September, 1965/Bhadra 31, 1887, it is notified for general information that Shri Sachindra Chaudhuri, Minister of Finance, Government of India and Shri O. V. Alagesan, Minister of Petroleum & Chemicals, Government of India, New Delhi have been nominated as members of the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research with immediate effect, till 31st March, 1968.

S. HUSAIN ZAHEER, Secy., (Ex-Officio)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th March 1966

SUBJECT:—Central Advisory Board of Museums—Reconstitution of the—

No. F. 12-3/65(i)-C.3.—In supersession of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Education No. F. 12-1/63-C.3, dated 2nd February 1963, read with the Ministry of Education Notification Nos. 33-13/55 dated 8th February 1956 and 33-39/56-C.3 dated 31st October 1956, it is hereby resolved that the Central Advisory Board of Museums be reconstituted as follows to advise the Government of India on matters related to the Reorganisation and Development of Museums and to promote closer contacts between different Museums and closer association of Government and Public with the activities of different Museums in the country:—

2. Name :

The Board shall be called Central Advisory Board of Museums.

3. Composition :

The composition of the Board shall be as follows:—

- (i) Secretary, Ministry of Education (in-charge of the Museums)—Chairman of the Board (Ex-Officio);

- (ii) Vice-Chairman to be elected by the Board from among its members;
- (iii) Not more than four nominees of the Government of India;
- (iv) Joint Secretary or Joint Educational Adviser concerned with Museums;
- (v) Director General of Archaeology in India;
- (vi) A nominee of the Lalit Kala Akademi;
- (vii) Director, National Museum, New Delhi or if there is no Director, the senior most officer in charge of the museum;
- (viii) Director, Salar Jung Museum, Hyderabad, or if there is no Director, the senior most officer-in-charge of the museum;
- (ix) Director, National Gallery of Modern Art, New Delhi, or if there is no Director, the senior most technical officer-in-charge of the Gallery;
- (x) Director, Indian Museum, Calcutta, or, if there is no Director, the senior most technical officer of the museum, seniority to be determined according to the length of service as in charge of a section of the museum;
- (xi) Curator, Victoria Memorial Hall, Calcutta;
- (xii) Director, Prince of Wales Museum of Western India, Bombay;
- (xiii) A representative to be nominated by each State Government, who should normally be the Curator of the State Museum or some one active in the museum field;
- (xiv) Not more than three persons possessing special knowledge of museums co-opted by the Board;
- (xv) Member-Secretary, to be nominated by the Government of India;

NOTE: The expression 'Curator' wherever it is used above, shall include the Director or the senior most officer in charge of the museum by whatever designation he may be called.

4. Term of Office

- (a) The term of office of the members, including the Vice-Chairman but excluding the Chairman and *ex-officio* members and the Secretary of the Board, shall be three years from the date of nomination or such shorter term as may be co-terminous with the term of the Board. The term of the office of the Chairman and *ex-officio* Members shall be three years or for so long as they hold office by virtue of which they are members of the Board whichever is less. Secretary shall also hold office for a period of three years from the date of the constitution of the Board or during the pleasure of the Government whichever is less. The term of office of a member nominated to a casual vacancy shall be the same as the unexpired portion of the term of membership of the original member.
- (b) Nominated members shall be eligible for re-nomination.

5. Functions

The Board shall advise the Government of India, the State Governments and the Museums in India on all matters pertaining to Museums referred to it by the authorities concerned and shall offer advice regarding the improvement, re-organisation, popularisation and development of the Museums generally.

6. Meetings

The Board shall meet as and when considered necessary by the Chairman. There shall be at least one meeting in a year. Special meetings may be called on a requisition by at least one-third of the members, provided that the requisition reaches the Secretary not less than a month before the meeting is to be convened and is accompanied by a clear statement of the business to be transacted.

7. Notice of Meetings

The Secretary shall send notice of meeting together with the agenda, to the members at least 15 days before the meeting.

8. Quorum

At least one-third of the members shall be present to constitute a quorum. Where for lack of a quorum a meeting is adjourned, no quorum shall apply for the adjourned meeting.

9. Standing and Ad Hoc Committees

(1) The Board will be at liberty to form standing or *ad hoc* Committees and will have power to appoint to an *ad hoc* Committee persons who are not members of the Board but who possess special knowledge and experience of the problems which the Committee will be required to examine.

(2) Pending the election of the Standing Committee by the Board, such members of the last Standing Committee as will be returned to the Board now constituted will perform the functions of the Committee.

(3) Pending the Co-option of fresh members, under sub-para (xiv) of para 3 above, the members co-opted by the previous Board shall continue to be members of the new Board till the finish of the first meeting of the new Board.

10. Dissolution and Reconstitution

The Board may be dissolved or re-constituted at any time at the discretion of the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution may be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. F.12-3/65(ii)-C.3.—In pursuance of the Government of India, Ministry of Education Resolution No. F.12-3/65(i)-C.3 dated the 28th March, 1966 the following persons have been nominated to be members of the Central Advisory Board of Museums for a period of three years with effect from 28th March, 1966 :—

I. Under Clause (iii) of para 3 of the Resolution (Nominees of the Government of India) :—

1. Shri Rai Krishna Dasa,
Hony. Director,
Bharat Kala Bhavan,
Banaras Hindu University,
Varanasi (U.P.).
2. Dr. (Mrs.) Grace Morley,
New Delhi.
3. Shri Karl J. Khandalawala,
Silverene,
63, Worli Sea Face,
Bombay-18.
4. Dr. S. Nurul Hasan,
Head of the Department of History,
Aligarh Muslim University,
Aligarh (U.P.).

II. Under Clause (vi) of para 3 of the Resolution (Nominee of the Lalit Kala Akademi) :—

- Shri G. Venkatachalam,
6, St. John's Road,
Bangalore.

III. Under Clause (xiii) of para 3 of the Resolution (Nominee of the State Governments) :—

1. Andhra Pradesh—Shri M. A. Waheed Khan, Director of Archaeology and Museums, Hyderabad.
2. Assam—Shri Premdhar Chaudhuri, Curator, Assam State Museum, Gauhati.
3. Bihar—Shri P. L. Gupta, Curator, Patna Museum, Patna.
4. Gujarat—Shri V. L. Devkar, Director, Museum and Picture Gallery, Baroda.
5. Kerala—Shri K. Parameswaran Pillai, Director of Museums and Zoos, Government of Kerala, Trivandrum.
6. Madhya Pradesh—Shri Balchand Jain, Deputy Director of Museum, Raipur.
7. Madras—Shri S. T. Satyamurti, Director of Museums, Madras.
8. Maharashtra—Dr. M. G. Dikshit, Director of Archives and Historical Monuments, Bombay.
9. Mysore—Shri K. Manikyam, Curator, Bangalore Museum, Bangalore.

IV. Under Clause (xv) of para 3 of the Resolution (Member-Secretary) :—

- Deputy Secretary (Cultural Division),
Ministry of Education,
New Delhi.

T. S. KRISHNAMURTI, Dy. Secy.

New Delhi, the 30th March 1966

SUBJECT :—National Council for Rural Higher Education—

No. F.1-2/66-U3.—In continuation of this Ministry's notification No. F. 1-2/64-U3 dated 30th September, 1965, on the above subject, it is hereby notified that the term of the National Council for Rural Higher Education is further extended for a period of three months with effect from 1st April, 1966.

G. K. CHANDIRAMANI, Additional Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION**(Department of Transport, Shipping and Tourism)****(Transport Wing)****RESOLUTIONS***New Delhi, the 24th March 1966***CENTRAL INLAND WATER TRANSPORT BOARD**

No. 7-IWT(7)/65.—The Government of India attach great importance to the development and expansion of inland water transport which has, an important role to play in the economy of this country. There are immense potentialities for developing inland water transport in India as there are several rivers and canals on which navigational facilities can be provided for the carriage of goods as well as passenger traffic.

A recent review of the inland water transport schemes included in the Third Five Year Plan has revealed that the progress in the execution of these schemes could be expedited.

As many of the schemes relating to inland water transport cover more than one State, close coordination between the State Governments concerned is essential in order to ensure proper planning and execution of these schemes. To achieve this, the Government of India have decided to set up a Central Inland Water Transport Board with the following composition :—

Chairman

1. Secretary, Department of Transport, Shipping and Tourism, Ministry of Transport and Aviation.

Members

2. Member (WR) Central Water & Power Commission, Ministry of Irrigation and Power.
3. Development Adviser, Ministry of Transport and Aviation.
4. Nautical Adviser, Directorate General of Shipping.
5. Chief Surveyor, Directorate General of Shipping.
6. One representative each of the Governments of Assam, West Bengal, Orissa, Bihar, U.P., Maharashtra, Gujarat, Kerala, Madras, Andhra Pradesh and Goa.
7. One representative each of the Ministry of Railways and the Ministry of Defence.
8. Two Technical engineers with experience of inland waterways (to be nominated by the Ministry of Transport and Aviation).

Member-Secretary

9. Chief Engineer (Director), Inland Water Transport Directorate, Ministry of Transport and Aviation.

The Chief Engineer of the State concerned will be co-opted when matters relating to that State are considered.

The functions of the Central Inland Water Transport Board will be as follows :—

- (i) to discuss and coordinate matters relating to inland water transport;
- (ii) to advise the Central and State Governments on problems concerning this mode of transport; and
- (iii) to periodically review the progress made in the execution of inland water transport schemes and suggest measures with a view to ensuring their speedy execution.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Planning Commission and the Ministries of the Government of India as well as the State Governments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 21-T(42)/64.—Dr. V. G. Bhatia, Director, Transport Research in the Ministry of Transport and Aviation (Department of Transport, Shipping & Tourism) has been nominated, with immediate effect, as a member of the Road Transport Taxation Enquiry Committee set up *vide* this Ministry's Resolution No. 21-T(42)/64, dated the 6th September, 1965.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and also that it be published in the Gazette of India for general information.

PORTS*New Delhi, the 28th March 1966*

No. 2-PG(55)/65.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Kandla for the year 1964-65. The salient features of the Report are reviewed below :—

(1) Financial Results

(a) *Port Fund* : The revenue receipts of the port (excluding the Pilotage Account) during the year were 121.42 lakhs as compared with Rs. 114.42 lakhs during 1963-64. A

higher receipt figure is partly due to amalgamation of Township accounts with the Port Accounts, and partly due to larger revenues from Lands and Buildings.

The expenditure (excluding that charged to the Pilotage Account and contributions to the Depreciation Fund, Revenue Reserve Fund and Capital Account) during the year under review was Rs. 82.63 lakhs as against 62.25 lakhs in 1963-64. The percentage of working expenses (excluding the amounts transferred to the Depreciation Fund, Revenue Reserve Fund and Capital Account) to income under the General Account was 68 as against 55 in the previous year. The increase in expenditure was mainly due to increased expenditure on dredging, payment of arrears of water and electricity charges, amalgamation of revenue expenditure on township, enhanced dearness allowance, payment of interest on Provident Fund balances etc. The contribution made to the Depreciation Fund, Revenue Reserve Fund and Capital Account were Rs. 55.51 lakhs, Rs. 22.50 lakhs and Rs. 40.00 lakhs respectively, during the year 1964-65.

(b) *Pilotage Account* : The gross income and expenditure during 1964-65 was Rs. 3.48 lakhs and Rs. 2.43 lakhs (excluding a contribution of Rs. 8,000 to the Depreciation Fund in the Pilotage Account), respectively, resulting in a surplus of Rs. 1.05 lakhs. There was a surplus of Rs. 1 lakh in 1963-64, the gross income and expenditure for that year being Rs. 2.80 lakhs and Rs. 1.80 lakhs respectively.

(c) *Debt* : The outstanding debt of the Port Administration at the close of the financial year 1964-65 was Rs. 16.77 crores due to the Government of India on account of assets transferred to the Port Administration and a loan of Rs. 22.00 lakhs advanced to them to finance their Capital works. This also includes an amount of Rs. 26.74 lakhs on account of the assets taken over from the former Government of Kutch.

(2) Traffic

(a) *Trade* : The traffic which passed through the Port of Kandla in 1964-65, as compared with that in 1963-64, is indicated in the table below :—

Year	Imports	Exports	Total Traffic
	(In lakhs of Metric tonnes)		
1963-64	14.91	2.88	17.79
1964-65	20.54	2.58	23.12

The imports during the year under report registered an increase of 5.63 lakhs metric tonnes or about 37.8% of the imports of the previous year. This increase was mainly due to increased imports of foodgrains and machinery. The exports in 1964-65 registered a fall of 0.30 lakh metric tonnes as compared with the exports in 1963-64 mainly due to less traffic in ores, cotton, wool etc.

(b) *Shipping* : Excluding sailing vessels, 343 vessels, with a gross tonnage of 28.87 lakhs, entered the port during 1964-65 as against 297 vessels with a gross tonnage of 24.26 lakhs in 1963-64.

M.T. "Mount Vernon Victory" of 27,412.64 tons gross, 224.40 metres length, 31.26 metres beam, 9.69 M. Fore and 9.75 Metres Aft. draft was the biggest and longest vessel that entered the Port during 1964-65.

S.S. "Columbia" of 14,462.82 tons gross, 174.65 Metres length 10.11 M. Fore and 10.11 M. Aft. draft was the deepest vessel that entered the Port during 1964-65.

(3) Labour

The labour situation in the port continued to be satisfactory during 1964-65.

(4) Capital Works

The construction of a fishing jetty was completed during the year under review. The fifth cargo berth adding 1,125 feet of quayage was completed except for dredging. The activities of the soil and water testing laboratory and the photographic section continued. On the soil testing side, bore holes over the site of construction of 327 quarters at Kandla were taken.

(5) Welfare activities

The Port Organisation continued to provide their staff with various amenities such as housing, consumer cooperative stores, educational facilities, clubs, canteens, medical facilities etc., during the year under review. A cooperative credit society has also been formed and is functioning successfully.

(6) The work of development of the Gandhidham township progressed satisfactorily during the year.

(7) Acknowledgement

Government views with appreciation the work of the Port Trust during the year under review.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and also published in the Gazette of India.

K. C. MADAPPA, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

RESOLUTION

Cash Prize for the best feature film on national unity and emotional integration

New Delhi-1, the 21st March 1966

No. 7/17/65-F.I.—With a view to encourage the production of feature films aimed at promoting national unity and emotional integration in the country, Government have instituted a cash prize of Rs. 20,000.

2. The Award will be given in respect of the best feature film on the above theme out of films certified for public exhibition by the Central Board of Film Censors during the calendar year 1966.

3. Entries for the Award will be invited by Government by a prescribed date, to be notified in December, 1966.

4. Only such films will be eligible for receiving the award as have secured one of the State Awards for Films instituted by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting or achieved a run of 12 weeks by the date of their entry for the Award.

5. The entry of films for this Award will be governed *mutatis mutandis* by the Rules concerning the State Awards for Films notified in the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 7/19/64-F.I., dated the 21st November, 1964 as amended from time to time.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. R. KHANNA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st March 1966

No. WB-19(2)/65.—In pursuance of the recommendations made in para 25 of Chapter XXVII of the Second Five Year Plan and in para 20 of Chapter XV of the Third Five Year Plan, the Government of India have decided to set up a Central Wage Board for the Leather and leather goods industry.

2. The composition of the Wage Board will be as follows :—

Chairman

Shri M. Sriramamurty.

Independent Members

Shri T. Jijyar Das.

Dr. D. L. Narayana.

Members Representing Employers

Shri Haji Mohamed Sami.

Shri A. Mohd. Ghouse.

Members Representing Workers

Shri Ramanand Das.

Shri Sailen Paul.

3. The following will be the terms of reference of the Board :—

- to determine the categories of employees (manual, clerical, supervisory, etc.) who should be brought within the scope of the proposed wage fixation;
- to work out a wage structure based on the principles of fair wages as set forth in the Report of the Committee on Fair Wages; as conditions and problems in Tanneries differ substantially from those in leather and foot-wear industries, the Board shall take into account such differences while making its recommendations, and if necessary evolve separate Wage structures for these two industries.

Explanation : In evolving a wage structure, the Board will take into account, in addition to the considerations relating to fair wages;—

- the needs of the industry in a developing economy including the need for maintaining and promoting exports;
- the requirements of social justice;
- the need for adjusting wage differentials in such a manner as to provide incentive to workers for advancing their skill;
- the special features of the leather and leather goods industry; and
- the desirability of extending the system of payment by results.

Explanation : In applying the system of payment by results, the Board shall keep in view the need for fixing a minimum (full-back wage) and also to safeguard against over-work and undue speed.

4. The coverage of the Wage Board will be restricted to establishments employing 20 or more workers.

5. The Board may consider the demands of labour for the grant of interim relief and make recommendations thereon. While recommending such interim relief, the Board will take into account the different levels of wages in various units of the industry.

6. The headquarters of the Board will be located at Madras. The correspondence intended for the Board shall be addressed to the Chairman, Central Wage Board for Leather and leather goods industry, 'Lemon House', No. 5, Venkatarayana Road, T. Nagar, Madras-17.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. C. MATHEW, Secy.

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi-11, the 26th March 1966

No. 11(8)/66-RH.II.—Shri F. H. Vallabhoy, Joint Secretary, Ministry of Finance (Rehabilitation Division), Government of India has been nominated, with immediate effect, as a Member of the Committee of Direction set up in terms of the Government of India, Ministry of Rehabilitation's Resolution No. 29(13)/64-RR/Rehab.II, dated the 25th November, 1965, *vice* Shri D. J. Madan, Joint Secretary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

- All State Governments and all Chief Commissioners.
- All Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Union Public Service Commission, the Cabinet Secretariat, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all Accountant General and Comptrollers, Chief Pay and Accounts Officer, Department of Supply and Technical Development, Pay and Accounts Officer, Ministries of Works and Housing and Rehabilitation, Railway Ministry (Railway Board), Director General of Supplies and Disposal.
- All Members of the Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

L. J. JOHNSON, Additional Secy.